गन्ना मिल मालिकों की नयी नौटंकी

अब गन्ने की किस्मों को लेकर मिल मालिकों ने एक नयी नौटंकी शुरू की है। इन्होंने गन्ने की 7 प्रजातियों 91269, 90260, 8102, बी ओ 91, 1148 और 92423 को अपनी मर्जी से बेकार घोषित कर दिया है। मिल मालिक सरकार पर इन किस्मों को खारिज करने या इनका भाव 15 रुपये प्रति कुन्तल कम करने के लिये दबाव डाल रहे हैं। प्रदेश के एक तिहाई में लगभग 7 करोड़ बीघे रकबा इन्हीं किस्मों की फसल लगी है। किसान सालों से इन किस्मों को बो रहे हैं। मिल मालिकों ने बीच सीजन में अब एक नया झमेला पैदा कर दिया है।

मिल मालिकों का कहना है कि इन किस्मों से चीनी कम निकलती है। इसलिये ये बेकार हैं। इनसे हमें घाटा होता है। जबकि किसानों का कहना है कि हम सालों से इन किस्मों को बो रहे हैं। ये किस्में हमने तैयार नहीं की हैं। इन्हें देश के विद्वान कृषि वैज्ञानिकों ने सरकारी गन्ना शोध केन्द्रों में तैयार किया है। मिल मालिकों ने हर साल कुछ किस्मों को बेकार घोषित करना अपना धंधा बना लिया है। हर साल नये और बेहद महंगे बीज लाकर बोने का हमारा ब्योंत नहीं है।

मिल मालिकों का इन किस्मों को कम रिकवरी (चीनी) के आधार पर बेकार कहना सरासर गलत है। क्योंकि जबसे मिलें लगी हैं (तब से आज तक रिकवरी के आधार पर गन्ने का भाव तय करने का कोई क़ानून नहीं है और समर्थन मूल्य भी रिकवरी के आधार पर तय नहीं होता है।)

चीनी के उत्पादन करने में गन्ना उगाने का असली बुनियादी काम किसान करता है। इसलिये उसका हक़ पहले है। इन किस्मों में रोग कम लगता है। जिससे खाद और कीटनाशकों की कम जरूरत होती है। दूसरा ये किस्में कम पानी मांगती हैं जिससे ज़मीन के बेशकीमती पानी की बचत होती है। ये दोनों ही बातें ज़मीन व पर्यावरण दोनों के लिये फ़ायदेमंद हैं। इसका फ़ायदा पूरी इंसानियत को है। इसलिये किसान को हक़ है कि वह इन किस्मों को बोये।

मिल मालिक हर साल कुछ किस्मों को बेकार बताकर रिजेक्ट खाते में डलवा देते हैं। इससे किसानों को हर साल नये बीज बोने पड़ते हैं। इनकी कीमत घर के बीज से कई गुणा ज़्यादा होती है। खुद मिल मालिक भी अपने फ़ार्मों में तैयार बीज को कई गुणा कीमत पर बेचते हैं। मिलों के सुझाये बीज़ों में चीनी तो बेशक थोड़ी ज्यादा निकलती है, लेकिन उनमें रोग बहुत अधिक लगते हैं, पानी की जरूरत ज्यादा होती है, जंगली पशुओं (सुअर, नील गाय, गौदड़ आदि) से नुकसान बहुत ज्यादा होता है। और वे मौसम की ऊंच-नीच को भी नहीं झेल पाते। इन सब वजहों से इनका उत्पादन बहुत कम होता है, इसलिये इनसे केवल चंद मिल मालिकों को फ़ायदा है और बाकी करोड़ों किसानों और जनता को नुकसान है।

किस्मों के इस नये बतंगड़ के अलावा भी मिल मालिक रोज़ ब रोज़ किसानों को कभी जड़ साफ़ न होने को लेकर, कभी छोल साफ़ न होने की बात कहकर परेशान कर रहे हैं। इसके अलावा तौल केन्द्रों घटतौली भी खुलेआम चल रही है जिसे लेकर आये दिन झगड़े होते हैं। मिल मालिकों द्वारा की जा रही इस नयी नौटंकी के पीछे की सच्चाई कुछ और है। (इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने मिल मालिकों को किसानों के बकाया का भुगतान सितम्बर 2014 तक करने का आदेश दिया था। लेकिन सरकार से हज़ारों करोड़ की छूट लेने के बावजूद उन्होंने आज तक भी पूरा भुगतान नहीं किया है।) दूसरे सरकार ने मौजूदा गन्ना सीजन के लिये मिलों को 240 रुपये कुन्तल का भुगतान गन्ना लेने के 14 दिन के अन्दर और बाकी 40 रुपये कुन्तल का भुगतान तीन महीने के अन्दर करने का आदेश दिया था इसमें भी कुन्तल पर 40 रुपये सरकार देगी (जनता की गाढ़ी कमाई से) इतने बड़े फ़ायदे के बावजूद मिलों ने इस आदेश को भी ठेंगे पर रख दिया। किसान समय से आये भुगतान की मांग न कर सकें इसलिये मिल मालिक यह नयी चाल चल रहे हैं।

हाल ही में प्रदेश के गन्ना शोध केन्द्रों और सरकारी फ़ार्मों ने बताया है कि एक कुन्तल गन्ना पैदा करने पर 253 रुपये का खर्चा आता है। अगर इसमें गन्ना छोलने और तोल केन्द्र तक की ढुलाई का खर्चा भी जोड़ दें तो यह खर्च 293 रुपये कुन्तल हो जायेगा। किसानों का 70 फ़ीसदी गन्ना तौल केन्द्रों से जाता है जहां पर अगेती किस्म का दाम कुन्तल पर 12 रुपये का भाड़ा व कर्दा काटकर 268 रुपये कुन्तल मिलता है। अगर इसमें से 15 रुपये घटा दें तो यह केवल 253 रुपये कुन्तल पड़ेगा। मिल मालिकों के घाटे की भरपाई तो सरकार जनता के पैसे से कर देगी, लेकिन किसानों का क्या होगा। दूसरों की जिन्दगी में मिठास घोलने वाले किसान आखिर कब तक कड़वी घूंट पीते रहेंगे?

- किसान

पूंजीपतियों मालिकों, ठेकेदारों के राज में मज़दूरों की बढ़ती दुर्दशा

आज देश के अंदर पूंजीपतियों, मालिकों, ठेकेदारी प्रथा के राज में मज़दूरों की दुर्दशा दिन पर दिन हो रही है। चाहे वह संगठित क्षेत्र के मज़दूर हों चाहे फ़िर असंगठित क्षेत्र के मज़दूर हों और दिहाड़ी मज़दूरों की हालत तो और भी बुरी है। जिन्हें कई-कई दिन तक काम ही नहीं मिलता। सुबह टिफिन बांधकर निकलते हैं और ऐसे ही लौट आते हैं। जिनका सुबह को चूल्हा जल गया तो शाम को चूल्हा जलने की गारण्टी नहीं है। नरेगा के मज़दूरों का भी बुरा हाल है। आखिर काम करवाकर क्यों मालिक, पूंजीपति, ठेकेदार, मज़दूरों का पैसा देना अच्छा नहीं समझता? क्यों मज़दूरों को आम गुलामी जैसी जिन्दगी जीनी पड़ती है। क्यों उनकी तरफ कोई भी देखना नहीं चाहता? क्यों सरकारें मज़दूरों के पक्ष को नहीं देखती हैं। ये सोचने का विषय है।

धनवान कहते हैं कि मज़दूर वे लोग होते हैं जो बोडम होते हैं। यानि कि मज़दूरी वही करते हैं जिनके पास दिमाग नहीं होता है। और जिनके पास दिमाग होता है। वह अपना व्यवसाय करते हैं। मज़दूर वह शख्स है जो आठ-दस घण्टे काम करके 400 से 500 रुपये कमाकर शराब पीकर आराम से सोता है। उन्हें कोई चिन्ता नहीं होती है।

ये बातें वे लोग करते हैं जो ज्यादा रईस होते हैं। जिनकी वजह से मज़दूर बुरी तरह की जिन्दगी जीने के लिये विवश होते हैं। आप मेरे साथ एक महीना फैक्टरी में काम करके देखें, पढे-लिखे मज़दूर भी मिल जायेंगे। जो फैक्टरी में काम करना ही नहीं जानते बल्कि वे देश का शासन भी चला सकते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है। पैक्टरियों में माल पैदा नहीं होगा, मज़दूर काम नहीं करेगा तो आपका बिजनिस भी नहीं होगा ये बात आपको समझनी चाहिए- पैसे की कमी के कारण मज़दूर ज्यादा पढ नहीं पाता, इसका मतलब यह नहीं कि वह बोडम है। या वह सिर्फ मज़दूरी ही कर सकता है। इस पर वह व्यक्ति चुप्पी साध गया और दूसरी तरफ़ मुंह करके बैठ गया- हमें अपनी बात को पुरज़ोर तरीके से रखनी चाहिये।

यहां किसी एक फैक्टरी या अन्य औद्योगिक कामों के क्षेत्र में हो रही मज़दूरों के शोषण की घटनाओं के विस्तार को बताने का सवाल नहीं है क्योंकि काम का कोई भी क्षेत्र है उसमें सिर्फ़ उत्पादन और मुनाफ़े से मतलब है। मज़दूर काम करते-करते मर जाता है तो उसको वहीं भट्टी में झोंक देते हैं। या उसको कहीं अन्यत्र फेंक देते हैं। आये दिन जो कारखानों में मज़दूरों के शोषण की घटनायें होती हैं। वह स्पष्ट तौर पर अखबारों, टीवी चैनलों का हिस्सा ही नहीं बन पाती जिनका पता नहीं चलता। किसी तरह से चलता भी है तो मालिक ठेकेदार उसको रफ़ा दफ़ा करने में अपना पल्ला छुड़ाने में कोई कोताही नहीं बरतता और सरकार भी उसे पूरा बचाने का काम करती है।

देश के अन्दर नई आर्थिक नीतियों के कारण ठेकेदारी प्रथा के कारण नयी आर्थिक गुलामी बढ़ रही है जिससे आज का मज़दूर गुलामी की ओर बढ रहा है। जिसका कहीं कोई निदान पूंजीपतियों, मुनाफ़ाखोरों की व्यवस्था में नहीं दिखता। श्रम कानूनों में परिवर्तन अथवा सुधार के नाम पर मोदी सरकार ने देशी-विदेशी पूंजीपतियों, मालिकों, ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के कारण आज़ादी में मिले अधिकारों को भी छीन लिया है। हर तरफ़ सस्ते श्रम की लूट के लिए नियमों को लचीला किया है। आज मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं एक बड़ी गुलामी को देश के अन्दर बढावा दे रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देश में बढावा दे रहे हैं। वे कहते हैं कि देश के अन्दर रोज़गार के अवसर खुलेंगे। जब अपने देश के कारखानों में ही मज़दूरों को स्थायी रोज़गार नहीं दे सकते तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में रोजगार की क्या गारण्टी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो दुनिया में मुनाफ़े की लूट मचाने, हत्यायें करवाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि बनाते हैं। प्रधानमंत्री को अपने देश के अंदर कोई मुख्य अतिथि बनाने लायक नहीं मिला। बेहद शर्मनाक है। पैसे और मुनाफ़े पर टिकी इस व्यवस्था में सरकारों से मेहनतकश मज़दूरों-किसानों को किसी प्रकार की अभिलाषा करना बेकार है। मज़दूरों को संगठित होकर अपने ऊपर हो रहे शोषण के खिलाफ़ बतौर एक वर्ग देश के अन्दर उठ खड़ा होना होगा और शोषण के खिलाफ़ हो रहे विरोधों को तेज़ करना होगा। क्योंकि ठेकेदार मालिक मज़दूरों पर दया खाकर शोषण करना बन्द नहीं करेंगे उन्हें मुनाफ़ा चाहिए होता है। मज़दूर की जिन्दगी से मतलब नहीं होता है। वह उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक देते हैं। शोषण को खत्म करना है तो मज़दूरों को ही उनके राज को खत्म कर अपना राज कायम करना पड़ेगा। वह राज जिसमें किसी का शोषण न हो, इसके लिये मेहनतकशों के संगठन और उनकी विचारधारा के साथ जुड़ा होना व कदम बढाना जरूरी है।

-नागरिक

कभी जल का सम्मान हमारे संस्कारों में हुआ करता था

आज जल संस्कृति से विमुक्त होते नौजवानों के पीछे प्रमुख कारण आधुनिक शिक्षा में प्रकृति के प्रति प्रेम और परिश्रम का कम होना है। इस कारण प्रकृति के साथ पानी के लेने और देने के हमारे जो रिश्ते थे, वो भी टूट गए हैं। पहले गर्मी के दिनों में पूरा गांव पानी से पहले ताल बांधने का काम करता था। आजकल यह परम्परा छूट गई है। अब लोग पानी की बोतल खरीदकर पीना चाहते हैं। पानी का यह नया बाजार हमें निजीकरण के मोह में फंसा लिया है।

पहले बचपन में दादा-दादी, नाना-नानी सब अपने बच्चों को सिखाते थे कि तुम्हारे जीवन के लिए पानी निश्चित है। वे सिखाते थे कि अपने जीवन में पानी उतना ही इस्तेमाल करना जिससे बर्बाद न हो। इस चाल-चलन के कारण पानी के प्रति सम्मान था। लिहाजा पानी के स्रोत ताल तलैयों के प्रति भी लोगों का सम्मान था। इसीलिए जन्म से लेकर मरण तक विवाह आदि तक सभी संस्कार ताल-पोखर के पास हुआ करते थे। ये संस्कार पानी के प्रति युवाओं के मन में सम्मान पैदा करते थे और पानी के सदुपयोग का चलन आ जाता था। जिससे पानी के कम उपयोग की आदत इनके मन में होती थी। साथ ही साथ ताल-तलैयों को गंदा न करने का संस्कार भी विकसित होता था। उसी के साथ पानी के सदुपयोग और पुन: उपयोग करने की आदत विकसित होती थी। ये आदत ताल तलैयों को पुनर्जीवित करने का चलन बनाकर रखती थी। युवाओं की बेरुखी के कारण आज हमारे ताल-तलैये मर गए हैं। 21वीं सदी के दूसरे दशक में यदि हमने अपनी जल स्रोतों की इस विरासत को पुनर्जीवित नहीं किया तो हम अपने वालों दिनों में बेपानी हो जाएंगे। हमारी जिंदगी में लाचारी, बेकारी और बीमारी आ जाएगी। इसलिए हमें अपने ताल तलैयों को पुनर्जीवित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। आज से ही हम अपने संस्कार और व्यवहार में और अपनी शिक्षा में ताल तलैयों के उपयोग को बढ़ावा दें। आज देश में जल संस्कृति को वापस लाने की जरूरत हैं। इस हेतु देश के सभी संतों, महंतों, मठों को जल साक्षरता के लिए पानी के प्राण है, के अध्यात्म दर्शन द्वारा एक नई चेतना जगाने के जरूरत है। हमारा आज का अध्यात्म पुराने ज्ञान और विज्ञान के साथ गहरा रिश्ता रखता है। हमने नीर, नारी और नदी इन तीनों को पूर्ण सम्मान दिया था और इनका रक्षण संरक्षण संवर्द्धन सतत् किया था। जब तक हमने यह किया तब तक हम दुनिया के गुरू बने रहें। हमें अब फिर वहीं करना होता। हमें जन्म देने वाली धरती माता उसमें जीवन की शुरुआत करने वाले जल और वायु पर अब बहुत बड़ा खतरा है। इस खतरे से बचने की चेतना जगाने की दक्षता और क्षमता करने वाले जल और वायु पर अब बहुत बड़ा खतरा है। इस खबरे से बचने की चेतना जगाने की दक्षता और क्षमता हमारी शिक्षा में नहीं है। इसीलिए भारतीय ज्ञानतंत्र और हमारी गुरु परम्परा दुबारा से पानी से प्राण डाल सकती है। इसलिए हमें एक बार फिर अपने नीर, नारी और प्रकृति और नदी (जीवन का प्रवाह) को सम्मान देने की शुरूआत करनी होगी। राजस्थान के समाज ने अपनी सात नदियों का पुनर्जीवित करके यह करिश्मा कर दिखाया है। मैंने पिछले माह गणतंत्र दिवस पर पूरे देश में इसी काम को फैलने के लिए श्री गेरे मठ चित्रदुर्ग जिला कर्नाटक से ऐसी ही शुरुआत की है। इसमें हम युवाओं को विद्यालयों में जाकर तथा ग्रामीणों को गांव-गांव जाकर तालाबों को नदियों के साथ जोड़ने के लिए पदयात्रा, वाहन यात्रा और जल साक्षरता यात्रा शुरू की है। आज इस तरह की चेतना देश भर में खड़ी करने की जरूरत है। इसी प्रकार भारत सरकार और सभी राज्य सरकारें अपने शिक्षा के पाठ्यक्रम में नीर, नारी और नदी के शिक्षण पाठ्यक्रम शुरू कर दें तो पुनः तरुणों और युवा में ताल तलैयों के प्रति प्रेम बढ़ेगा और राष्ट्र में एक जल चेतना खड़ी होगी।

- कमल किशोर

तुर्की-ब-तुर्की

रामपुर की बालमीकि बस्ती को धराशाही करने के मन्त्री आजम खां के मंसूबों पर वहां के बाशिंदों ने पानी फ़ेर दिया। उन्होंने इसके लिये धर्मांतरण के हथियार का इस्तेमाल किया जो राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक के ध्रुवीकरण के लिये करती हैं।

हमारा कहना है:-

- रामपुर के बालमीकियों ने एक ही वार से आजम खां की स्कीम ही फ़ेल नहीं कर दी बल्कि विहिप व भाजपा जैसे साम्प्रदायिक दलों के भी 'घर वापसी' अभियान की भी हवा निकाल दी। आजम खां और अखिलेश सरकार को अपने बुलडोज़र वापस बुलाने पड़े। जबकि आर एस एस और विहिप की सरगर्मियां भी उनके पक्ष में सक्रिय दिखीं, बिना धर्मान्तरण का मुद्दा साम्प्रदायिक कलेवर में लपेटे।
- विहिप और आर एस एस का खेल रहा है कि गरीब और लाचार मुसलमानों व ईसाइयों को लालच/धमकी देकर घर वापसी का स्वांग रचाना। चार लाख प्रति घर वापसी के नाम पर खर्च दिखा कर ये हिन्दुत्व के ठेकेदार कम से कम तीन लाख प्रति घर वापसी अपनी जेब में डाल लेते हैं। इस कवायद में मीडिया और अपनी मशीनरी के सहयोग से साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा किया जाता है। जाहिर है इसका चुनावी लाभ भाजपा को मिलता है। रामपुर के बालमीकियों ने इसी रणनीति को भाजपा के मुंह पर दे मारा।
- तमाचा तो मन्त्री आजम खां और अखिलेश सरकार के मुंह पर भी लगा। बालमीकियों ने मुसलमान बनने की धमकी देकर उनके घुटने भी टिकवा दिये। आजम खां को अपनी 'भलमनसाहत' सिद्ध करने के लिये देश छोड़ने तक की धमकी देनी पड़ी। अखिलेश को पक्का वादा करना पड़ा कि जब तक बालमीकियों के लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर दी जाती उन्हें मॉल के नाम पर बेदखल नहीं किया जायेगा।
- उसे कहते हैं नहले पे दहला यानी राजनीतिकों का जूता राजनीतिकों का सर।

रामपुर के बालमीकि

जब तक सियासतदां खेलता है
धर्मान्तरण का खेल
पार्टियां बांटती रहती हैं
और हर टोली बंट जाती है
जब खेलने पर आते हैं
लाचार बाल्मीकि
रामपुर में यही खेल
पार्टियां बगलें झांकती हैं
उनकी रणनीति की फट जाती है

-विकास नारायण राय